

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी*

एम. राजेश्वर राव

कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, आईबीबीआई, श्री सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई, विशिष्ट अतिथिगण, पैनल सदस्यों और शोधकर्ताओं, देवियों और सज्जनों,

सबसे पहले, मैं इस सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मेलन काफी उपयुक्त रूप से एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक - तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर केंद्रित है। यदि मैं यह कहूँ कि भारत पिछले कुछ वर्षों में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में विनियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है, तो यह कोई न्यूनोक्ति नहीं होगी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का भारत में लेनदार-देनदार संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संहिता के तहत कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित और कार्यान्वित किए पांच वर्षों से भी अधिक समय हो गया है, और यह अब तक हुई प्रगति और भविष्य के बारे में अपेक्षाओं का जायजा लेने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

ऋण शोधन अक्षमता और उसका समाधान

किसी भी ऋणदाता के लिए, क्रेडिट जोखिम, यानी अनुबंधित राशि का समय पर पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं होने की संभावना या प्रतिपक्ष द्वारा क्रेडिट अनुबंध के संबंध में अपने दायित्वों का पूरा नहीं करने की संभावना, एक महत्वपूर्ण जोखिम का गठन करती है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखने और जोखिम प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। सैद्धांतिक रूप

* आईआईएम, अहमदाबाद में आयोजित दिवाला और शोधन अक्षमता पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा 30 अप्रैल 2022 द्वारा की गई टिप्पणियाँ। हम श्री वैभव चतुर्वेदी, श्री सूरज मेनन और श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

में, एक उधारकर्ता तब चूक करता है जब वह अपने व्यवसाय से अपर्याप्त नकदी प्रवाह के कारण अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है या उसकी आस्तियों का बाजार मूल्य उसकी देयताओं के मूल्य से कम हो जाता है, जो उसकी आस्त को परिसमाप्त करने और कोई चूक न हो- यह सुनिश्चित करने के लिए लेनदारों को भुगतान करने की उधारकर्ताओं की क्षमता में बाधा डालता है। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से, वास्तविक दुनिया की स्थितियों में यह पता लगाना आसान नहीं है कि क्या कोई उधारकर्ता डिफॉल्ट होने तक दिवालिया हो गया है। प्रायः, तब तक उधारकर्ता की आस्त का विपणन योग्य मूल्य उसकी देयताओं से पहले ही कम हो चुका होगा। चूंकि उधारकर्ता की देनदारियाँ ऋणदाता के लिए आस्त के रूप में हैं, उधारकर्ता की अपनी देयताओं का भुगतान करने में असमर्थता से ऋणदाता की आस्त का मूल्य कम हो जाएगा जिससे उनके लेनदारों को चुकाने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी, जिसमें बैंकों के मामले में मुख्य रूप से जमाकर्ता शामिल हैं। यही मुख्य कारण है कि आरबीआई विनियमित संस्थाओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समय पर समाधान में रुचि रखता है। यहां तक कि जहां ऋणदाता कोई बैंक नहीं है, वित्तीय प्रणाली की परस्पर संबद्धता से अप्रत्यक्ष प्रभाव होंगे जो वित्तीय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

एक बार जब कोई उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है, तो लेनदारों की स्वाभाविक प्रवृत्ति संबंधित उधारकर्ता की बिक्री योग्य आस्त के शेष हिस्से के सबसे बड़े संभव अंश के लिए जल्दबाजी करके अपने नुकसान में कमी लाना है। हालांकि, हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि दिवालियेपन की स्थिति का तात्पर्य यह नहीं है कि उधारकर्ता की भविष्य की संभावनाएं मौजूद नहीं हैं - कई मामलों में कर्ज का एक विवेकपूर्ण पुनर्संतुलन इसे वापस ट्रैक पर लाने के लिए पर्याप्त होगा - जब तक कि वित्तीय दबाव अत्यंत तीव्र न हो। एक कार्यशील संस्था लगभग हमेशा ही एक परिसमाप्त कंपनी की तुलना में एक लेनदार (ऋणदाता) के लिए अधिक मूल्यवान होनी चाहिए। इस संदर्भ में एक व्यापक दिवाला समाधान कानून महत्वपूर्ण बन पड़ता है।

इस प्रकार, एक प्रभावी ऋण शोधन अक्षमता कानून निम्नलिखित पांच स्तंभों पर आधारित होना चाहिए:

- I. इसे परिसमापन पर कार्यशील संस्था की स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- II. इसे लेनदारों को एक साथ मिलकर एक समाधान योजना तैयार करने के लिए बाध्य करना चाहिए जो कंपनी को चालू रखने के लिए विकल्पों को देखकर कार्यशील संस्था को संरक्षित करने का प्रयास करता है।
- III. इसे एक समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि एक दिवालिया एक्सपोजर के लेनदारों के मूल्य हास को रोका जा सके।
- IV. इसे चूककर्ता उधारकर्ता के वित्तीय दबाव में योगदान देने वाले संदिग्ध लेन-देनों का पता लगाना चाहिए,
- V. अंत में, यदि बहुमत का निर्णय अनुमोदन की पूर्वनिर्धारित सीमा को कवर करता है, तो एक प्रभावी समाधान व्यवस्था को शोधन अक्षमता से अविकल्पी सौदे के रूप में बाध्य कर बहुमत की अल्पसंख्यकों से रक्षा करनी चाहिए।

उपरोक्त पांच सिद्धांतों के अलावा, समाधान फ्रेमवर्क को उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा की गुणवत्ता के आधार पर वित्तीय लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच भी अंतर करना चाहिए क्योंकि क्रेडिट साधन के प्रारंभिक मूल्य निर्धारण ने सुरक्षा की उपलब्धता में फेक्टर किया हो सकता है, और यदि समाधान मूल्य में शेयर का निर्धारण करते समय ऐसी सुरक्षा की गणना नहीं की जाती है तो ऋणदाता को नुकसान होगा। इस तरह के एक व्यवस्था की अनुपस्थिति में, लेनदारों को उनके द्वारा उठाए जा रहे क्रेडिट जोखिमों के लिए उच्च मुआवजे की मांग करने की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र क्रेडिट लागत बढ़ जाती है।

जबकि किसी भी समाधान फ्रेमवर्क को फर्म के मूल्य को संरक्षित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही, “परिसमापन की कगार पर कार्यशील संस्था” एक पूर्ण प्राथमिकता नहीं हो सकती है। उत्पादन के अनुत्पादक या पुराने कारकों को नियोजित करने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, परिसमापन ऐसे उद्यमों में फंसे मूल्य को अनलॉक करने में मदद कर सकता है और फिर अधिक दक्ष और उत्पादक उद्यमों की सहायता के लिए पुनर्निर्माण किया जा सकता है। “बाहर निकलने में आसानी” के अभाव में, एक अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन क्षमता, अक्षम

व्यावसायिक उद्यमों के लिए बंधक बन जाएगी और अर्थव्यवस्था को अपनी संभाव्यता तक पहुंचने से रोक देगी। इस प्रकार, एक प्रभावी शोधन अक्षमता कानून को उपक्रमों के परिसमापन से पीछे नहीं हटना चाहिए, जब उन्हें समाज के लिए महंगे साबित होते हैं और पुनर्नियोजन के लिए मूल्य को अनलॉक करना अधिक फायदेमंद होगा।

वर्ष 2016 से पहले शोधन अक्षमता समाधान

2016 में आईबीसी के अधिनियमन से पहले भारत में बहुत सारे कानून थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक उधारकर्ता के शोधन अक्षमता समाधान की प्रक्रिया पर आंशिक अधिकार क्षेत्र था। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) 1985 में अधिनियमित किया गया था और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना की गई थी। इसके बाद, डीआरटी को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय कर्जों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था (कर्जों की वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 के रूप में फिर से नाम दिया गया)। वर्ष 2002 में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी- एसएआरएफईएसआई) को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हितों के तेजी से प्रवर्तन के लिए अधिनियमित किया गया था।

हालांकि इन कानूनों का उनके लागू होने के बाद की प्रारंभिक अवधि में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, पर समय के साथ सुधार कम होते गए। इसके अलावा, पूर्व-आईबीसी समाधान प्रयासों का ध्यान कंपनियों और रोजगार के संरक्षण की ओर अधिक था, कभी-कभी क्रेडिट अनुशासन और अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता की कीमत को भी ताक पर रख दिया जाता था।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों का समय पर समाधान आरबीआई के लिए महत्वपूर्ण रुचि रखता है। एक व्यापक शोधन अक्षमता कानून के अभाव में, आरबीआई को ऐसी योजनाओं की एक श्रृंखला बनानी पड़ी, जो एक शोधन अक्षमता कानून की वांछनीय विशेषताओं का अनुकरण करती हैं। इस प्रकार, पहले के विनियमनों ने संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम के गठन को अनिवार्य कर दिया, जिसकी आईबीसी के तहत

लेनदारों की समिति के समान भूमिका थी। आस्ति वर्गीकरण ठहराव आईबीसी के तहत घोषित अधिस्थगन के बराबर था। बहुमत के निर्णय के लिए असहमति वाले लेनदारों पर बाध्यकारी होने की आवश्यकता, आईबीसी के तहत अविकल्पी सांविधिक संकट के एक विनियामक समकक्ष थी।

हालांकि, वित्तीय प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आरबीआई की सांविधिक शक्तियां आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं तक सीमित हैं, जबकि वित्तीय अनुबंधों के जटिल जाल को खोलना और उन्हें एक दिवालिया देनदार की आय सृजन क्षमताओं के अनुरूप पुनर्लेखन करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेनदारों पर व्यापक शक्तियों के साथ व्यापक वैधानिक ढांचे की आवश्यकता है। हालांकि, अच्छे अभिप्राय से आरबीआई द्वारा डिजाइन की गई योजनाएं कभी-कभी वास्तविक आस्ति वर्गीकरण को स्थगित करके उधारकर्ताओं में वित्तीय तनाव की पहचान में देरी करने के लिए उधारदाताओं के लिए एक माध्यम बन जाती हैं।

आईबीसी के तहत महत्वपूर्ण बदलाव

वर्ष 2016 में आईबीसी के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की दिशा में प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। संहिता ने प्रचलित दृष्टिकोणों से अलग एक क्रांतिकारी रुख अपनाया, जिसमें उसने “क्रेडिटर-इन-कंट्रोल” मॉडल को “डेटर इन पोसेशन” मॉडल के खिलाफ अपनाया, जो देश में क्रेडिट अनुशासन में कोई ठोस सुधार करने में विफल रहा था। इस प्रकार, संहिता मूल रूप से देनदारों और लेनदारों के बीच देनदारों द्वारा एक चूक की स्थिति में शक्ति संतुलन को रीसेट करती है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से सुदृढ़ है क्योंकि लेनदारों के पास केवल एक उधारकर्ता द्वारा बनाए गए आर्थिक अधिशेष का अनुबंधित हिस्सा होता है, शेष अधिशेष बिना किसी सीमा के इक्विटी धारकों के पास चूक (डिफॉल्ट) न होने की स्थिति तक जाता है। उस समय इक्विटी धारकों को सीमित देयता द्वारा संरक्षित किया जाता है, जबकि लेनदारों को दिवालिया देनदार के प्रति अपने संपूर्ण एक्सपोजर तक खोने का जोखिम होता है। एक ही बार में संहिता ने “प्रवर्तकों के नियंत्रण में बने रहने के दैवीय अधिकार” को हटा दिया जिससे अन्य हितधारकों, विशेष रूप से लेनदारों के हितों को बहाल होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था।

धारा 29ए के सम्मिलन ने इस धारणा को और बल प्रदान किया कि यदि आवश्यक हो, तो एक दिवालिया देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि देनदार से समग्र रूप से समाज के लिए मूल्य को अधिकतम किया जा सके। इस प्रकार, पहली बार यदि वित्तीय दबाव को समय पर और व्यापक तरीके से संबोधित नहीं किया जाता है, तो प्रवर्तकों (प्रमोटर) को अपनी संबंधित कंपनियों पर नियंत्रण खोने की संभावना का सामना करना पड़ा।

संहिता ने एक सार्वजनिक संस्था के रूप में लेनदारों की समिति की भी स्थापना की, जिसमें एक कॉर्पोरेट देनदार के समाधान के दौरान हितधारकों के लिए मूल्य का अधिकतमकरण सुनिश्चित करने की सर्वोपरि जिम्मेदारी थी। लेनदारों की समिति में केवल वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं, जिसे व्यापक सार्वजनिक हित के समक्ष अपने व्यक्तिगत हितों को गौण मानना पड़ता है, यह अन्य समान कानूनों की तुलना में संहिता की एक अनूठी विशेषता है।

संहिता ने परिचालन लेनदारों की बातचीत करने की शक्ति को भी बढ़ाया, जिससे उन्हें डिफॉल्ट में परिचालन देनदारों के संबंध में सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली। 31 दिसंबर 2021 तक कुल सीआईआरपी मामलों में से 51% से अधिक मामले परिचालन लेनदारों द्वारा दायर किए गए थे। ऐसे मामलों में आहरण का अनुपात भी अधिक था - 50% से अधिक, कुल आहरण मामलों का 71% - यह दर्शाता है कि एक बातचीत कार्यनीति के रूप में शोधन अक्षमता कार्यवाही दाखिल करना परिचालन लेनदारों के लिए कारगर प्रतीत होते दिखा रहा है।

आईबीसी के तहत हुए प्रस्तावों में लिये गए उच्च स्तर के हेयरकट के बारे में लेनदारों को कुछ चिंताएं हैं। इन चर्चाओं में, हम इस तथ्य को याद करते हैं कि सार्वजनिक बोली-आधारित समाधान मॉडल में, हेयरकट (मार्जिन) की सीमा एक दिवालिया उधारकर्ता में निवेश जारी रखने के लिए बाजार की मांग में छूट का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि दिवालिया उधारकर्ता की आस्ति में महत्वपूर्ण मूल्य गिरावट हो सकती है, बकाया राशि के साथ तुलना समाधान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक उचित संकेतक नहीं हो सकता है।

बल्कि, लेनदारों के लिए समाधान मूल्यों की तुलना अगले सर्वोत्तम विकल्प से की जानी चाहिए, जो इस मामले में परिसमापन है। जिन सीआईआरपी मामलों का समाधान हुआ है, उनमें से देनदारों के परिसमापन मूल्य की तुलना में वित्तीय लेनदार 166% की वसूली करने में सक्षम रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि लेनदार अगले तार्किक परिणाम से बेहतर रहे हैं।

संहिता के प्रभाव से संबंधित एक अन्य अक्सर उपेक्षित पहलू विश्वसनीय 'दिवालियापन का खतरा' है। इस प्रभाव का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण माप सीआईआरपी आवेदनों की संख्या है, जो प्रविष्ट होने से पहले वापस ले लिए जाते हैं। दिसंबर 2021 तक, सीआईआरपी शुरू करने के लिए 19,803 आवेदनों, जिनका कुल अंतर्निहित डिफॉल्ट ₹6.1 लाख करोड़ था, का प्रवेश से पहले समाधान किया गया था। संहिता के अभाव में, इसकी अधिक संभावना रहती है कि ये चूक (डिफॉल्ट) बहुत लंबे समय तक बनी रहे, जिससे मूल्य का हास होता है।

आरबीआई और आईबीसी

भले ही संहिता के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की सीआईआरपी में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, लेकिन आरबीआई विनियमित ऋण प्रणाली एक प्रभावी दिवालियापन कानून का एक महत्वपूर्ण हितधारक है। क्रेडिट मध्यस्थहीनता के बढ़ते स्तरों के साथ, आईबीसी देनदारों के व्यापक समाधान के लिए उपलब्ध सबसे पसंदीदा साधन बन गया है।

यह तथ्य कि लंबे समय से चले आ रहे दबाव के समाधान को प्रोत्साहन देने के लिए संहिता का लाभ उठाया जा सकता है, इसे संहिता के तहत सीआईआरपी से संबंधित प्रावधानों की अधिसूचना के लगभग तुरंत बाद पहचाना गया था। इसकी परिणति बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 में हुई, जिसने आरबीआई को आईबीसी के तहत समाधान के लिए विशिष्ट डिफॉल्ट मामलों को संदर्भित करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया। इन शक्तियों के तहत, जैसा कि अब व्यापक रूप से विदित है, आरबीआई ने जून 2017 में बैंकों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत 12 सबसे बड़े देनदारों के संबंध में आईबीसी के तहत शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद अगस्त 2017 में फिर से निर्देश दिये गए,

जहां बैंकों को डिफॉल्ट रूप से अन्य 29 कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में समयबद्ध समाधान योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू की जानी थी।

आईबीसी के अधिनियमन और कानून के तहत दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए ट्रिगर होने के कारण डिफॉल्ट घटना ने अनिवार्य समाधान के लिए नियामकीय ट्रिगर पर भी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। हमने 7 जून, 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्तियों (प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क) के समाधान के लिए एक सरल और सामंजस्यपूर्ण विवेकपूर्ण ढांचे के साथ पुनर्गठन के लिए सभी प्रचलित योजनाओं को बदल दिया, जिसमें निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत शामिल थे:

- बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी द्वारा बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में चूक की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग।
- विनिर्दिष्ट समय-सीमा और स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन के अधीन, समाधान योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में ऋणदाताओं के लिए पूर्ण विवेक का साथ।
- समाधान योजना के कार्यान्वयन या दिवाला कार्यवाही शुरू करने में देरी के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के रूप में दंड की एक प्रणाली।
- पुनर्चना पर आरिस्त वर्गीकरण छूट को वापस लेना। उचित अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के सार्थक होने पर भविष्य में आरिस्त का उन्नयन।
- पुनर्चना के उद्देश्य से, 'वित्तीय कठिनाई' की परिभाषा को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा गया था; तथा,
- सभी ऋणदाताओं द्वारा अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया था, जो बहुमत वाले निर्णय लेने का मानदंड प्रदान करेगा।

आईबीसी के बाहर दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की दिशा में आरबीआई का दृष्टिकोण समाधान प्रयासों को समय पर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना रहा है; ऋण पुनर्रचना के रूप में दी गई रियायतों के कारण ऋणदाताओं को बढ़े हुए ऋण जोखिम की उचित पहचान; और उधारकर्ताओं को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि रियायतों ने ऋण पुनर्रचना के बाद एक उचित अवधि के दौरान अपने ऋण दायित्वों पर संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करके उनकी व्यवहार्यता में सुधार किया है।

ऋण शोधन अक्षमता फ्रेमवर्क से अपेक्षाएं

आईबीसी जैसा आधुनिक दिवाला कानून को सभी हितधारकों के समर्थन और धैर्य की जरूरत है और नए कानून के प्रति रवैया केवल लंबे समय से दबाव वाली आस्तियों के समाधान के संबंध में होने वाले नुकसान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। साथ ही, यह आवश्यक है कि विनियमित संस्थाओं के विभिन्न वर्गों में व्यवस्थाओं के उपयुक्त सामंजस्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए ढांचे की आवधिक समीक्षा के माध्यम से अदालत के बाहर के प्रस्तावों के लिए नियामक व्यवस्था में सुधार जारी रखा जाए। मुझे लगता है कि संहिता को और मजबूत करने के लिए, हमें निम्नलिखित चार आयामों पर काम करने की आवश्यकता है:

ए. समाधान में बड़ी तरवीर: आईबीसी जैसे व्यापक कानून को अक्सर ऋणदाताओं द्वारा अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है - एक ऐसा मार्ग जिसे सभी विकल्पों के निष्फल हो जाने के बाद प्रयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह दृष्टिकोण संकटग्रस्त उधारकर्ता के भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टि की कमी से उपजा है। ऋणदाताओं के विभिन्न वर्ग अदालत के बाहर के समाधान ढांचे के अलग-अलग सेट द्वारा शासित होते हैं जो ऋणदाता के प्रत्येक वर्ग पर अलग से लागू होते हैं। सभी ऋणदाताओं की भागीदारी के बिना, समाधान की दिशा में कोई भी प्रयास अधूरा होने की संभावना है और यह अपरिहार्य नुकसान का एक स्थगन मात्र होगा। इस तरह के अधूरे प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में लगने वाला समय लेनदारों को होने वाले

नुकसान और वित्तीय प्रणाली की लागत को बढ़ाने वाले हैं। चूंकि यह एक शोध सम्मेलन है, इसलिए मैं एक शोध प्रश्न का प्रस्ताव देना चाहता हूँ: एक उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट और लेनदारों द्वारा दिवाला समाधान के लिए आवेदन दाखिल करने के बीच औसत समय क्या है? आवेदन दर्ज कराने में इस तरह की देरी और मूल्य में गिरावट के बीच संबंध को देखना भी दिलचस्प होगा जिसे लेनदारों को बाद में ध्यान में रखना होगा।

बी. दिवाला आवेदनों के दाखिल होने में देरी: एक और विचलित करने वाला पहलू दिवाला आवेदन दाखिल करने और आवेदन के अंतिम स्वीकृति के बीच लगने वाला समय है। संहिता 14 दिनों की अवधि निर्धारित करती है। हालांकि, वास्तव में, स्वीकृति में आमतौर पर उससे अधिक समय लगता है। आईबीबीआई द्वारा 13 अप्रैल, 2022 को जारी एक परामर्श पत्र में कहा गया है कि किसी परिचालन लेनदार के दिवाला आवेदन की स्वीकृति के लिए लिया गया औसत समय 2020-21 में 468 दिनों से बढ़कर 2021-22 में 650 दिन हो गया है। यह संहिता के तहत एक सीआईआरपी को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा से भी अधिक है। आवेदन स्वीकृति में इस तरह की देरी से व्यापक दिवालियापन कानून के रूप में आईबीसी की दक्षता कम होने की संभावना है और इससे लेनदार के अधिकार कमजोर हो सकते हैं और दिवालिया उधारकर्ताओं के लिए बाहर निकलने में आसानी हो सकती है। यहां एक और शोध प्रश्न है: दिवाला आवेदनों की स्वीकृति में देरी के लिए जिम्मेदार कारक और आईबीसी का सहारा लेने वाले उन लेनदारों की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की संभावना जिनके आवेदनों में देरी हुई है।

सी. प्री-पैक समाधानों के कवरेज में वृद्धि: किसी भी कानून की तरह, आईबीसी को भी बदलते आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ विकसित होने की जरूरत है। आईबीबीआई की सक्षम नियामक क्षमताओं द्वारा निर्देशित दिवाला कानून पर स्थायी समिति के रूप में

वर्तमान समीक्षा ढांचा, इसे सुनिश्चित करने का एक अनुकरणीय कार्य कर रही है। आईबीसी के लिए नए आयाम पेश किए जा रहे हैं जैसे कि प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (पीपीआईआरपी/प्री-पैक) का नया मॉड्यूल, जो कोर्ट के बाहर के समाधान प्रयासों और स्वीकृत समाधान योजनाओं की न्यायिक प्रक्रिया की पूर्णता को जोड़ती है, जो कि एक निर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वागत योग्य पहल है। भले ही पीपीआईआरपी को वर्तमान में केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के लिए अनुमति दी गई है, हम प्री-पैक की कल्पना गैर-सहकारी से जुड़े उस कठिन समाधान में सभी उधारकर्ताओं के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण ढांचे के प्राकृतिक पूरक के रूप में कर सकते हैं। उधारदाताओं को ऐसी पूर्व-पैकेज्ड योजनाओं का उपयोग करके समाधान किया जा सकता है। सभी उधारकर्ताओं के लिए पीपीआईआरपी का विस्तार करने पर विचार करना सार्थक होगा।

डी. समूह के लिए समाधान: एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जिसे संहिता में शामिल करने की आवश्यकता है, वह है समूह के लिए समाधान की अवधारणा - ऐसा जिसमें एक ही कॉरपोरेट समूह से संबंधित उधारकर्ताओं का समाधान एक साथ किया जाता है। इसका एक उदाहरण हमने वीडियोकॉन समूह की समाधान प्रक्रिया के दौरान देखा; हालाँकि, इसे संहिता की एक विशेषता के बजाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपलब्ध विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से किया गया था। ऐसी प्रक्रिया भारत जैसी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां परंपरागत रूप से ऋण अनुबंधों को परस्पर दायित्वों और उधारकर्ता की मूल और समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए ऋण न्यूनीकरण कवर के साथ जोड़ा गया है। ऐसी प्रणाली में, उधारकर्ता द्वारा चूक से समूह की कंपनियों द्वारा परस्पर चूक को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे वित्तीय प्रणाली के लिए समग्र ऋण जोखिम बढ़ जाता है। इस प्रकार संहिता की प्रभावकारिता में और सुधार करने के लिए ऐसे परस्पर

जुड़े कॉरपोरेट समूहों के सामूहिक समाधान के लिए एक व्यापक प्रक्रिया आवश्यक है।

ऋणदाताओं से अपेक्षाएं

भारत में ऋण जोखिम बाजार का गहरा होना वित्तीय प्रणाली को परिष्कार के अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। आरबीआई हाल के वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठा रहा है। ऋण जोखिम के हस्तांतरण को कवर करने वाले दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है और सभी ऋणदाता संस्थानों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। दबावग्रस्त ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार को उन अंतरितियों के लिए खोल दिया गया है जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं। भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति (अध्यक्ष: डॉ हर्षवर्धन) और कॉरपोरेट ऋण के लिए माध्यमिक बाजार के विकास पर कार्य बल (अध्यक्ष: श्री टीएन मनोहरन) की सिफारिशों को विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है। कार्य बल की प्रमुख सिफारिशों में से एक - कॉरपोरेट ऋण हेतु द्वितीयक बाजार के लिए स्व-नियामक संगठन - माध्यमिक ऋण बाजार संघ की स्थापना के साथ लागू किया गया है। आरबीआई अतिरिक्त प्रकार के प्रतिभूतिकरण की अनुमति देने की व्यवहार्यता की खोज करके ऋण जोखिम बाजार को गहरा करने के लिए और रास्ते तलाश रहा है।

साथ ही, हम यह अपेक्षा करेंगे कि ऋणदाता समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए उधारकर्ता द्वारा चूक की प्रतीक्षा न करें। उधारदाताओं को अपने एक्सपोजर के विवेकपूर्ण जोखिम मूल्य निर्धारण को एक्सपोजर की निरंतर निगरानी और पर्याप्त पूंजी और जोखिम प्रावधानों के रखरखाव के साथ जोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी प्रतिपक्ष के दिवालिया होने के बिन्दु को सटीक रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है, उधारदाताओं के जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को जोखिम कारकों में परिवर्तन को पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत होना चाहिए जो उक्त ऋण जोखिम की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। ऋणदाताओं को संभावित प्रक्षेपवक्रों का अनुमान लगाने के लिए आवधिक दबाव परीक्षण भी करना चाहिए जो कि ऋण एक्सपोजर लेने की संभावना है और तदनुसार उनकी प्रतिक्रियाओं को परिवर्तित कर सके।

अंततः, वे अपने हित और अपने हितधारक के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, हमने देश में ऋण अनुशासन में सुधार लाने में एक लंबा सफर तय किया है।

हालांकि, किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह, यह हमेशा एक कार्य प्रगति पर स्थिति में होता है जिसमें किसी भी समय सुधार की गुंजाइश होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक समाधान ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखेगा और विभिन्न ऋण मध्यस्थों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली प्रणालीगत चिंताओं का ध्यान रखने के लिए लगातार अधिक परिष्कृत और अद्यतन जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाएगा। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं चाहता हूँ कि यह सम्मेलन अपनी तरह का पहला हो और अंतर्दृष्टिपूर्ण बहस उत्पन्न करे जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेगी।